वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.07.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", आई नेक्स्ट,भारत एकता टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

आई नेक्स्ट –दि0 08.07.2026

नोयडा की अपेक्षा काफी अधिक मिल रही भूमि की कीमत

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप आनंद काशी, रुद्र काशी, काशी स्पोर्ट्स सिटी के प्रगति से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा नोयडा से काफी अधिक भूमि की कीमत दी जा रही है. इसके बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें समझाएं.

: vcvdavns : Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

भारत एकता टाइम्स –दि0 08.07.2026

रोप-वे परियोजना के लिए वीडीए को 90 वर्ष की लीज पर भूमि आवंटित

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

रोप-वे पायलट परियोजना के निर्माण की राह अब और आसान हो गई है। टावर संख्या-29 एवं स्टेशन संख्या-5 के निर्माण के लिए कोतवालपुरा स्थित एक बिस्वा 19 धूर नजूल भूमि को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) को 90 वर्ष की लीज पर प्रतीकात्मक एक रुपये प्रीमियम के साथ आवंटित करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया है। इस प्रस्ताव को नगर विकास, वित्त और राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त है। भूमि का उपयोग केवल रोप-वे परियोजना के लिए किया जाएगा और यदि तीन वर्ष तक इसका उपयोग नहीं होता या उद्देश्य बदलता है, तो भूमि वापस ले ली जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार,

कोतवालपुरा स्थित नजूल आराजी संख्या-88 के कुल चार बिस्वा 19 धूर क्षेत्रफल में से एक बिस्वा 19 धूर भूमि रोप-वे परियोजना के टावर संख्या-29 और स्टेशन संख्या-5 के निर्माण के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण को 90 वर्ष की लीज पर प्रतीकात्मक एक रुपये प्रीमियम के साथ दी जाएगी। लीज का प्रत्येक 30 वर्ष पर नवीनीकरण होगा। सरकार ने वीडीए को सार्वजनिक इकाई मानते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है।